रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2015/ज्येष्ठ 11,1937
No. 355] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2015/JYAISTHA 11, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,1 जून, 2015

सा.का.नि.446(अ).-- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :--

"**सं.आ.267**"

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2015

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 270 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :--

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2015 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 270 के खंड (1) में निर्दिष्ट करों और शुल्कों के शुद्ध आगम का प्रतिशत, सेवाकर से भिन्न, जो उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित है, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किंतु 1 अप्रैल, 2020 से पहले समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, बयालीस प्रतिशत होगा जो निम्नलिखित रूप में राज्यों के मध्य वितरित होगा:

सारणी 1

(प्रतिशत)

राज्य	**राज्यों का अंश**
आंध्र प्रदेश	4.305
अरूणाचल प्रदेश	1.370
असम	3.311
बिहार	9.665
छत्तीसगढ़	3.080
गोवा	0.378
गुजरात	3.084
हरियाणा	1.084
हिमाचल प्रदेश	0.713
जम्मू-कश्मीर	1.854
झारखंड	3.139
कर्नाटक	4.713
केरल	2.500
मध्य प्रदेश	7.548
महाराष्ट्र	5.521
मणिपुर	0.617
मेघालय	0.642
मिजोरम	0.460
नागालैंड	0.498
ओडिशा	4.642
पंजाब	1.577
राजस्थान	5.495
सिक्किम	0.367
तमिलनाडु	4.023
तेलंगाना	2.437
त्रिपुरा	0.642
उत्तर प्रदेश	17.959
उत्तराखंड	1.052
पश्चिमी बंगाल	7.324

(2) सेवाकर के शुद्ध आगम का बयालीस प्रतिशत, अनुच्छेद 270 के खंड (1) में निर्दिष्ट कर होगा, जो उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित है, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किंतु 1 अप्रैल, 2020 से पहले समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित रूप में राज्यों के मध्य वितरित होगा :

सारणी 2

(प्रतिशत)

राज्य	राज्यों का अंश
आंध्र प्रदेश	4.398
अरूणाचल प्रदेश	1.431
असम	3.371
बिहार	9.787
छत्तीसगढ़	3.166
गोवा	0.379
गुजरात	3.172
हरियाणा	1.091
हिमाचल प्रदेश	0.722
झारखंड	3.198
कर्नाटक	4.822
केरल	2.526
मध्य प्रदेश	7.727
महाराष्ट्र	5.674
मणिपुर	0.623
मेघालय	0.650
मिजोरम	0.464
नागालैंड	0.503
ओडिशा	4.744
पंजाब	1.589
राजस्थान	5.647
सिक्किम	0.369
तमिलनाडु	4.104
तेलंगाना	2.499
त्रिपुरा	0.648
उत्तर प्रदेश	18.205
उत्तराखंड	1.068
पश्चिमी बंगाल	7.423

परंतु जहां अनुच्छेद 270 के खंड (1) के अधीन किसी वर्ष में सेवा कर जम्मू-कश्मीर राज्य में उद्गृहणीय हो जाता है प्रत्येक राज्य को जिसमें जम्मू-कश्मीर सम्मिलित हैं, वहां पैरा 3 के उपपैरा (1) की सारणी के स्तंभ (2) के सामने यथाविनिर्दिष्ट अंश दिया जाएगा ।

4. यदि 2015-2020 की अवधि के दौरान किसी वर्ष में, किसी राज्य में संघ के अधीन कोई कर उद्ग्रहीत नहीं है तो उक्त कर में उस राज्य का अंश शून्य होगा और संपूर्ण आगम आनुपातिक समायोजन द्वारा शेष राज्यों के मध्य वितरित होगा ।

5. संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 11 आदेश, 2010, 1 अप्रैल, 2015 से ही निरसित हो जाएगा ।

6. किसी राज्य को उसके हक से अधिक संदत्त कोई राशि या राशियां उसी या किसी पश्चातवर्ती वर्ष में वसूलनीय होंगी ।

प्रणव मुखर्जी,
राष्ट्रपति ।

[फा.सं.19(2)/15-वि.1]
डा. संजय सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2015

G.S.R. 446(E).— The following Order made by the President is published for general information:-

"C.O.267"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 2015

In exercise of the powers conferred by article 270 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Fourteenth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2015.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) The percentage of the net proceeds of taxes and duties referred to in clause (1) of article 270, other than the service tax, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2015 but ending before the 1st day of April, 2020, shall be forty-two per cent. which shall be distributed among the States as follows:—

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	4.305
Arunachal Pradesh	1.370
Assam	3.311
Bihar	9.665
Chhattisgarh	3.080
Goa	0.378
Gujarat	3.084
Haryana	1.084
Himachal Pradesh	0.713
Jammu and Kashmir	1.854
Jharkhand	3.139
Karnataka	4.713
Kerala	2.500
Madhya Pradesh	7.548
Maharashtra	5.521
Manipur	0.617
Meghalaya	0.642
Mizoram	0.460
Nagaland	0.498
Odisha	4.642
Punjab	1.577
Rajasthan	5.495
Sikkim	0.367
Tamil Nadu	4.023
Telangana	2.437
Tripura	0.642
Uttar Pradesh	17.959
Uttarakhand	1.052
West Bengal	7.324

(2) The forty-two per cent. of the net proceeds of the service tax, being the tax referred to in clause (1) of the article 270, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2015 but ending before the 1st day of April, 2020, shall be distributed among the States as follow:-

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	4.398
Arunachal Pradesh	1.431
Assam	3.371
Bihar	9.787
Chhattisgarh	3.166
Goa	0.379
Gujarat	3.172
Haryana	1.091
Himachal Pradesh	0.722
Jharkhand	3.198
Karnataka	4.822
Kerala	2.526
Madhya Pradesh	7.727
Maharashtra	5.674
Manipur	0.623
Meghalaya	0.650
Mizoram	0.464
Nagaland	0.503
Odisha	4.744
Punjab	1.589
Rajasthan	5.647
Sikkim	0.369
Tamil Nadu	4.104
Telangana	2.499
Tripura	0.648
Uttar Pradesh	18.205
Uttarakhand	1.068
West Bengal	7.423 :

Provided that where in any year the service tax under clause (1) of article 270 becomes leviable in the State of Jammu and Kashmir, each State including the State of Jammu and Kashmir shall be given a share as specified against it in column (2) of the Table to sub-paragraph (1) of paragraph 3.

4. If in any year during the period 2015-2020, a tax under Union is not leviable in a State, the share of that State in that tax shall be put to zero and the entire proceeds shall be distributed among the remaining States by proportionately adjusting their shares.

5. The Constitution (Distribution of Revenues) No. 11 Order, 2010, shall, as from the 1st day of April, 2015, stand repealed.

6. Any sum or sums paid to a State in excess of its entitlement shall be recoverable in the same or a subsequent year.

PRANAB MUKHERJEE,
President.

———

[F. No. 19(2)/15-L.I]

Dr.SANJAY SINGH,Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.